भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2364

03 दिसम्बर, 2019 के लिए प्रश्न

चावल की खरीद

2364. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चावल की आवश्यक मात्रा से अधिक चावल की खरीद कर रही है तथा यदि हां, तो गत दो वर्षों में चावल की खरीद के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान खराब हुए तथा निपटान किए गए चावल की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की चावल की खरीद को कम करने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन हेतु योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क): भारत सरकार की खरीद नीति के अधीन प्रत्येक विपणन मौसम (खरीफ/रबी) शुरू होने से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद की अवधि और गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों की घोषणा की जाती है। इसके अलावा, भारत सरकार की खरीद नीति खुली (ओपन एंडेड) होती है, जिसके अधीन निर्धारित अवधि के भीतर किसानों द्वारा जो भी धान लाई जाती है और जो भारत सरकार द्वारा अग्रिम तौर पर निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होती है, उसकी खरीद केन्द्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम सहित सरकारी एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर ली जाती है, ताकि किसानों को मजबूरन बिक्री से बचाया जा सके। पिछले 2 वर्षों के दौरान की गई चावल की खरीद का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख): वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भारतीय खाद्य निगम में क्षतिग्रस्त चावल की मात्रा और इसका निपटान निम्नानुसार है:

वर्ष	भारतीय खाद्य निगम में क्षतिग्रस्त चावल (टन में)	भारतीय खाद्य निगम में क्षतिग्रस्त चावल का निपटान (टन में)
2017-18	1844	830
2018-19	3793	2771

(ग): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 03.12.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 2364 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

पिछले दो वर्षों के दौरान की गई चावल की खरीद का विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**खरीफ विपणन मौसम 2017-18 (लाख टन में)**	**खरीफ विपणन मौसम 2018-19* (लाख टन में)**
आंध्र प्रदेश	40.00	48.06
तेलंगाना	36.18	51.86
असम	0.35	1.01
बिहार	7.93	9.49
चंडीगढ़	0.14	0.13
छत्तीसगढ़	32.55	39.71
गुजरात	0.01	0.09
हरियाणा	39.92	39.42
जम्मू और कश्मीर	0.13	0.09
झारखंड	1.43	1.53
कर्नाटक		0.59
केरल	3.29	4.65
मध्य प्रदेश	10.96	13.95
महाराष्ट्र	1.79	5.80
ओडिशा	32.87	44.48
पंजाब	118.33	113.34
एनईएफ (त्रिपुरा)		0.07
तमिलनाडु	10.11	12.94
उत्तर प्रदेश	28.75	32.33
उत्तराखंड	0.38	4.62
पश्चिम बंगाल	16.73	19.79
अखिल भारतीय योग :	**381.85**	**443.95**

* दिनांक 28.11.2019 की स्थिति के अनुसार

****